

लाट साहब बनेंगे कुंवर साहेब

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले कुंवर अर्जुन सिंह को हाशिए पर ले जाने की तैयारी आरंभ कर दी है। लंबे समय से अस्वस्थ रहने वाले पूर्व मानव संसाधन और विकास मंत्री अर्जुन सिंह को मनमोहन की पहली सूची में स्थान न मिलने से साफ हो गया है कि उनका राजनैतिक वजूद अब समाप्ति की ओर है। दो साल पूर्व भी उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनके विरोधियों ने उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल (लाटसाहब) बनाकर भेजने की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर दी थीं। उस दौरान अर्जुन सिंह ने साफ कहा था कि राज्यपाल बनने से बेहतर है कि वे सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लें। एक बार फिर वही इतिहास अब दोहराया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह और राजस्थान के शीश राम ओला दोनों ही को लाट साहब बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना यह है कि पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से राजनीतिक तूफान लाने वाले कुंवर साहेब कौन सा पैतरा चलते हैं।

चींटियों के रैले

यूपीए सरकार की दूसरी पारी में कई नये प्रयोगों को करने की बात की गई थी। मंत्रिमंडल के गठन में कुछ प्रयोग हुए भी हैं, लेकिन युवाओं को आगे लाने की बात जितने दमखम से की गई थी उसके अमल में उतनी कंजूसी बरती गई। एक डिपार्टमेंट की दो लोगों को जिम्मेदारी देने जैसे कई काम हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काम देखने व समझने के बाद ही आने वाले समय में युवाओं को स्वतंत्र कार्यभार मिल सकेगा। राहुल फैक्टर हालांकि हिट हुआ, लेकिन राहुल फिलहाल पार्टी की सेवा में ही लगे हैं। किसी प्रकार की जिम्मेदारी के बजाय वे बाहरी रणनीतियां बनाने में ज्यादा रूचि ले रहे हैं।

लोगों की जरूरतों को लेकर मंत्रियों ने घोषणाएं भी की हैं। जिसमें मुख्य रूप से संचार क्रांति पर जोर है। सब्जीवाले से लेकर कापेरिट तक मोबाइल सस्ते दरों पर इस्तेमाल कर सके, थे

उत्तम इंवर

व्यवस्थाएं होगी। मेडिकल क्रांति खेलों को बढ़ावा व व्यवसायों को बढ़ाने के वायदे किये गये हैं। ये वायदे कितने पूरे होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हालांकि वायदों की किस्मत टूट जाना होती है। इससे हम सभी वाकिफ हैं।

पाकिस्तान के हमले में लामबंद तालिबान के लिये कई कार्रवाई की जा रही है। इसमें कामयाबी के लिये सख्त कदम होना बहुत जरूरी रहेगा। यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार विश्व में अमन चैन हो इस बात पर काम किया जाए। पड़ोसी देश ही नहीं हमारे अपने शहरों की शांति को भी वैमनस्य का राक्षस लीलता जा रहा है। इंदौर में एक कांग्रेसी नेता की हत्या दो दिनों से शहर में चर्चा का विषय बनी है। हालांकि इस हत्या के बाद कई तथ्य सामने आ रहे हैं लेकिन शहर की फिजा, अमन-चैन, पानी सभी को कोई लीलता जा रहा है। नये मंत्रिमंडल के चयन के साथ आम लोगों ने बदलाव के बिगुल बजाए हैं। स्थितियां तो तब सुधरेगी जब अपने घरों से शुरूआत कर आसपास के वातावरण के संवारने का प्रयास होगा। अन्यथा मंत्रियों की फौज की तरह आने वाली नस्ल भी यूं ही लकीर पर रेंगती सी नजर आएगी। इन्हें नई व सही रात दिखाने के लिये चींटियों के इस रैले को आसमान से दोस्ती करनी होगी। यह बात देश की नहीं विश्वस्तर पर लागू हैं। जरूरत तो है बस एक और प्रयास की।



उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पुनः प्राप्त कर रही कांग्रेस के लिये उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल में पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाना भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। अपनी टीम गठन में मनमोहनसिंह ने इस बार अपनी पसंद और मर्जी को खूब तरजीह दी है और इसके चलते कुछेक मामलों में उन्होंने सोनिया गांधी की सिफारिश को भी दरकिनार किया है। बताते हैं कि सोनिया गांधी जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहती थी इस संबंध में उन्होंने मनमोहनसिंह को कहा भी था मगर दोनों को मामले में प्रधानमंत्री ने अपनी

मनमोहन टीम में रिश्तेदारों की जमावट

(दिल्ली ब्यूरो)

आखिरकार भारी मशक्कत मान-मनोव्वल और घटकों को चाहे गये मंत्री पद एवं विभाग देकर मनमोहनसिंह सरकार का पूरा मंत्रिमंडल तैयार करने में प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को काफी मशक्कत करना पड़ी। दोनों ने अपने सहयोगी घटक दलों और कांग्रेस के क्षेत्रों को राजी करने का प्रयास किया भी मगर फिर भी कई लोग नाराज हो ही गये। इनमें अर्जुनसिंह से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा और हंसराज भारद्वाज से लेकर शिवराज पाटिल तक कई नाम हैं। द्रमुक की नाराजी भले ही दूर हो मगर तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी पूरी तरह संतुष्ट हो पाई है यह दिखाई नहीं देता। खैर काफी जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल गठन कर मंत्रिमंडल में कई रंगों का समावेश किया। इसमें जहां रिश्ते नातेदारों की भरपूर जमावट है वहीं विभागों के असमान वितरण ने सभी को चौंकाया है।

मर्जी ही चलाई। जहां जयराम रमेश को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यमंत्री से ही संतोष करना पड़ा।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों और युवा सांसदों ने अच्छी सफलता अर्जित की। 43 महिला प्रत्याशियों में से 23 ने बाजी मार ली वहीं चालीस से कम उम्र के 79 सांसद चुने गये। इसे देखते हुए उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन कैबिनेट तो बुर्जुगवार सांसदों से भर गई वहीं अस्सी मंत्रियों में दर्जन भर युवा सांसद ही अपनी जगह बना पाए। नौजवान सांसदों

में अजय माकन, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां फिर से मंत्री बनाए गये हैं वहीं सचिन पायलट, अरूण यादव और प्रदीप जैन कांग्रेस खाते से नये मंत्री बने हैं। द्रमुक से ए.राजा, दयानिधि मारन को भी युवा मंत्रियों में जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या दर्जन भर से ज्यादा नहीं होती वहीं 9 महिलाएं ही मंत्रिमंडल में स्थान बना पाई हैं।

इस चुनाव में अल्पसंख्यक भले ही कांग्रेस की और लौटते दिखाई दे मगर मंत्रिमंडल गठन में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने में मनमोहन ने कंजूसी ही दिखाई है। पूरी कैबिनेट



में मुस्लिम समुदाय से एक कैबिनेट, एक राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्यमंत्री ही बनाये गये हैं।

शेष अंतिम पेज पर

वोट बैंक की खातिर भूरिया और यादव को मिला



मध्यप्रदेश से कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा। कैबिनेट मंत्री के तौर पर कमलनाथ और राज्यमंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनमोहन सिंह ने एक और मौका दिया तो आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया की पदोन्नति कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। वहीं नए और युवा चेहरे के रूप में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अरूण यादव को कैबिनेट में शामिल किया गया है। अलबत्ता, पूर्व में मनमोहन मंत्रिमंडल में शामिल रहे अर्जुन सिंह से कांग्रेस ने दूरी बनाई।

शेष अंतिम पेज पर

